नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 078
दि. 20.12.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

कड़वाहट से शुरु होकर गरम-मीठी चाय पर खत्म हुआ संसद का शीत सत्र

(जीएनएस)। नई दिल्ली। बिहार के चुनाव नतीजों के बाद बदले राजनीतिक समीकरणों, सत्तापक्ष के उत्साह और विपक्ष को लगे झटकों के बीच शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र आखिरकार एक असामान्य लेकिन सकारात्मक दृश्य के साथ समाप्त हुआ। जिस सत्र की शुरुआत तीखी बयानबाजी, आरोप-प्रत्यारोप और राजनीतिक तल्खी के साथ हुई थी, उसका समापन सरकार और विपक्ष के नेताओं द्वारा एक साथ बैठकर गरम-मीठी चाय की चुस्कियों और ठहाकों के साथ हुआ। बीते कुछ वर्षों में जहां अधिकांश सत्र कड़वाहट और टकराव के माहौल में खत्म होते रहे हैं, वहीं इस बार ठंड के मौसम में संसद के गलियारों में एक अलग ही सियासी गर्माहट देखने को मिली।

शीत सत्र की शुरुआत सरकार की ओर से 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने पर विशेष चर्चा और विपक्ष की ओर से एसआईआर सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर टकराव के साथ हुई थी। बिहार के चुनाव परिणामों और पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनावों को लेकर भी सदन के भीतर और बाहर जमकर राजनीति हुई। वंदे मातरम पर हुई बहस के दौरान गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का उल्लेख हो या फिर मनरेगा की जगह लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक पर महात्मा गांधी को लेकर छिड़ी सियासी बहस, पूरे सत्र में वैचारिक टकराव साफ नजर आया। इन दो बड़ी बहसों और दो अहम विधेयकों ने सत्र को राजनीतिक और विधायी दृष्टि से खास बना दिया। इस दौरान विपक्ष जहां सरकार की नीतियों का मुखर आलोचक बना रहा, वहीं कई मुद्दों पर उसने रचनात्मक रुख भी अपनाया। दूसरी ओर सरकार ने भी कई मौकों पर

अड़ियल रवैया दिखाया, लेकिन जरूरी विधायी कामकाज को आगे बढ़ाने में सकारात्मक रुख बनाए रखा।

इस सत्र का एक खास पहलू यह भी रहा कि राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन के रूप में यह पहला शीतकालीन सत्र था। उनके नेतृत्व में राज्यसभा की कार्यवाही अपेक्षाकृत सुचारु रही और कई संवेदनशील मुद्दों पर संतुलन बनाए रखने की कोशिश दिखाई दी। लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में गरमागरम बहसों के बावजूद संसदीय परंपराओं को निभाने का प्रयास किया गया।

सत्र के आखिरी दिन का दृश्य खासा चर्चा में रहा। लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में सरकार और समूचे विपक्ष के वरिष्ठ नेता एक साथ चाय पर बैठे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठीं और प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से लेकर अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड तक के विषयों पर चर्चा हुई। चाय के दौरान माहौल हल्का-फुल्का रहा और कई बार ठहाके भी लगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी के विदेश में होने और उप नेता गौरव गोगोई के सदन में मौजूद न रहने के कारण लोकसभा अध्यक्ष ने प्रियंका गांधी को अन्य विपक्षी नेताओं के साथ इस चाय बैठक के लिए आमंत्रित किया था। यह दृश्य हाल के वर्षों में संसद के इतिहास में दुर्लभ माना जा रहा है, जहां सत्र का समापन कड़वाहट के बजाय आपसी संवाद और सौहार्द के साथ हुआ।

विधायी कामकाज के लिहाज से भी यह शीत सत्र अहम रहा। इस दौरान कुल आठ महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें 2025-26 की अनुपूरक अनुदान मांगें शामिल रहीं। ग्रामीण भारत में 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाला विकसित भारत जी राम जी विधेयक, नागरिक परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देने वाला शांति विधेयक और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने वाला विधेयक प्रमुख रहे। सरकार का दावा है कि इससे बीमा कवरेज बढ़ेगा, प्रीमियम कम होंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा सबका बीमा सबकी रक्षा (संशोधन) विधेयक, 2025 को भी दोनों सदनों की मंजूरी मिली। पुराने और अप्रासंगिक 65 संशोधन कानूनों तथा छह मूल कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक भी पारित किया गया। मणिपुर जीएसटी संशोधन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर से जुड़े अन्य विधेयक भी इस सत्र में मंजूर हुए।

उच्च शिक्षा से जुड़े विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त समिति को भेजा गया। इस विधेयक का उद्देश्य एक उच्च शिक्षा आयोग और तीन अलग-अलग परिषदों की स्थापना करना है। वहीं, बाजार प्रतिभूति संहिता से संबंधित एक विधेयक पेश कर उसे स्थायी समिति के पास भेजा गया, ताकि उस पर विस्तार से विचार किया जा सके।

संसदीय कार्यवाही के आंकड़ों पर नजर डालें तो सत्र के दौरान 300 तारांकित प्रश्न स्वीकार किए गए, जिनमें से 72 के मौखिक उत्तर दिए गए। इसके अलावा 3,449 अतारांकित प्रश्नों को भी स्वीकार किया गया। शून्यकाल में 408 तात्कालिक मुद्दे उठे और नियम 377 के तहत 372 मामलों को सदन के पटल पर रखा गया। इन आंकड़ों से साफ है कि राजनीतिक टकराव के बावजूद संसदीय कामकाज पूरी तरह ठप नहीं हुआ।

कुल मिलाकर, संसद का यह शीतकालीन सत्र तीखे राजनीतिक हमलों, वैचारिक बहसों और अहम विधायी फैसलों के साथ-साथ एक सकारात्मक संदेश भी देकर गया। कड़वाहट से शुरू होकर गरम-मीठी चाय की चुस्की पर खत्म हुआ यह सत्र लोकतंत्र की उस परंपरा की याद दिलाता है, जहां मतभेदों के बावजूद संवाद और सहमति की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है।

तमिलनाडु चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़ा फेरबदल, लाखों नाम कटे,चुनाव आयोग ने जारी की ड्राफ्ट मतदाता सूची

(जीएनएस)। चेन्नई। तमिलनाडु में अगले वर्ष प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच भारतीय निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार, 19 दिसंबर को राज्य की एकीकृत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। यह सूची पूरे राज्य में चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन – एसआईआर) अभियान के बाद तैयार की गई है। जिला निर्वाचन कार्यालयों से सामने आए आंकड़ों के अनुसार, इस प्रक्रिया में तमिलनाडु के कई जिलों से लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा और चिंता दोनों बढ़ गई हैं।

ड्राफ्ट सूची के मुताबिक, कोयंबटूर जिले में करीब 6.50 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। वहीं डिंडीगुल जिले में 2.34 लाख वोटरों के नाम कटने के बाद कुल मतदाता संख्या 19.35 लाख से घटकर 16.09 लाख रह गई है। अन्य जिलों में भी बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने की पुष्टि हुई है, जिससे राज्यव्यापी आंकड़ा काफी अहम माना जा रहा है।

राज्य की राजधानी चेन्नई में इस पुनरीक्षण का सबसे बड़ा असर देखने को मिला है। यहां 14.25 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटा दिए गए हैं। इसके बाद चेन्नई में कुल मतदाता संख्या 40.04 लाख से घटकर 25.79 लाख रह गई है। करूर जिले में 79,690 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जिससे यहां मतदाता संख्या 8.79 लाख से घटकर 8.18 लाख हो गई। इसी तरह कांचीपुरम जिले में भी 2.74 लाख वोटरों के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं।

मतदाता सूची से इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने को लेकर चुनाव आयोग ने कारण भी स्पष्ट किए हैं। आयोग के अनुसार, पुनरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि 1.56 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा 27,323 मतदाता अपने पंजीकृत पते पर नहीं मिले। करीब 12.22 लाख मतदाता दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके थे, जबकि 18,772 मामलों में दोहरी मतदाता प्रविष्टियां पाई गईं, जिन्हें नियमों के तहत हटाया गया।

चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया है कि फिलहाल जारी की गई सूची ड्राफ्ट है। अब इस पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद सभी शिकायतों और संशोधनों के निपटारे के पश्चात अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। आयोग का कहना है कि इस पूरी कवायद का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और सुचारु रूप से कराए जा सकें।

हालांकि, लाखों नाम कटने के बाद राजनीतिक दलों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि अंतिम सूची में कितने नाम फिर से जोड़े जाते हैं और क्या इस प्रक्रिया को लेकर कोई बड़ा विवाद खड़ा होता है। आने वाले दिनों में मतदाता सूची को लेकर तमिलनाडु की राजनीति और अधिक गरमाने के संकेत मिल रहे हैं।

एक साल बाद कार्रवाई, कानून के रक्षक पर ही कानून का डंडा

(जीएनएस)। कोच्चि। केरल पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली एक घटना में आखिरकार एक साल बाद कार्रवाई हुई है। पिछले वर्ष कोच्चि में एक गर्भवती महिला पर कथित रूप से हाथ उठाने के मामले में थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई तब सामने आई, जब घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक हुई और उसमें पुलिस थाने के भीतर महिला के साथ दुर्व्यवहार साफ तौर पर दिखाई दिया। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि अलाप्पुझा जिले के अरूर पुलिस स्टेशन के एसएचओ प्रताप चंद्रन के.जे. को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

यह मामला 20 जून 2024 का है, जब प्रताप चंद्रन उस समय एर्नाकुलम नॉर्थ पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। कोच्चि की रहने वाली श्यामोल एन.जे. उस समय गर्भवती थीं और एक मामले के सिलसिले में उनके पति बेंजो को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पति से मिलने और स्थिति जानने के लिए श्यामोल पुलिस स्टेशन पहुंची थीं। आरोप है कि इसी दौरान पुलिस स्टेशन के भीतर विवाद हुआ और प्रताप चंद्रन ने श्यामोल के साथ न सिर्फ धक्का-मुक्की की, बल्कि उनके चेहरे पर थप्पड़ भी मारा।

गुरुवार को सामने आई सीसीटीवी फुटेज ने इन आरोपों को और गंभीर बना दिया। फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस स्टेशन के अंदर हुई झड़प के दौरान प्रताप चंद्रन श्यामोल को धक्का देते हैं और फिर उनके चेहरे पर थप्पड़ मारते हैं। इतना ही नहीं, फुटेज में एक महिला पुलिस अधिकारी भी श्यामोल को थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस महकमे पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया, जिसके बाद निलंबन का फैसला लिया गया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, निलंबन आदेश दक्षिण जोन के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। यह आदेश राज्य पुलिस प्रमुख रावड़ा चंद्रशेखर के निर्देशों पर पारित किया गया। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की विभागीय जांच भी की जाएगी और दोष सिद्ध होने पर और सख्त कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता।

इस बीच, पीड़िता श्यामोल और उनके पति बेंजो ने साफ शब्दों में कहा है कि वे इस मामले में पीछे हटने वाले नहीं हैं। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में दंपति ने कहा कि जब तक आरोपी अधिकारी को सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाता, तब तक वे अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। उनका कहना है कि एक गर्भवती महिला के साथ पुलिस स्टेशन के भीतर हुआ यह व्यवहार न सिर्फ अमानवीय है, बल्कि कानून और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन भी है।

यह मामला सामने आने के बाद केरल में पुलिस की जवाबदेही और महिला सुरक्षा को लेकर नई बहस छिड़ गई है। एक ओर जहां पुलिस को कानून का रक्षक माना जाता है, वहीं इस तरह की घटनाएं व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर करती हैं। सीसीटीवी फुटेज के सार्वजनिक होने के बाद अब यह मामला केवल एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे सिस्टम की संवेदनशीलता और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि विभागीय जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया इस मामले को किस अंजाम तक पहुंचाती है।

रूस-यूक्रेन युद्ध तुरंत रोकने को तैयार पुतिन,सुरक्षा गारंटी को बताया बड़ी शर्त

(जीएनएस)। मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध तुरंत रोकने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए सुरक्षा की ठोस गारंटी जरूरी होगी। पुतिन ने स्पष्ट किया कि यदि रूस की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, तो वह संघर्ष विराम और शांति की दिशा में आगे बढ़ने को तैयार हैं।

यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को लेकर पुतिन ने कहा कि अब तक यूक्रेन की ओर से पूरी तरह स्पष्ट और ठोस तत्परता नहीं दिखी है, लेकिन कुछ संकेत जरूर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कीव शासन की ओर से ऐसे संकेत मिल रहे हैं, जिनसे लगता है कि वे किसी न किसी रूप में बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं। पुतिन ने दोहराया कि रूस हमेशा से इस संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त करने की बात करता रहा है और आज भी उसी रुख पर कायम है।

इस दौरान रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए जा रहे कथित शांति प्रयासों का भी जिक्र किया। पुतिन ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ट्रंप के साथ हुई बैठक का हवाला देते हुए बताया कि एंकरिज में हुई बातचीत के दौरान रूस ने ट्रंप के प्रस्तावों पर सहमति जताई थी और व्यावहारिक रूप से उन्हें स्वीकार भी किया गया था।

पुतिन ने यह भी कहा कि यह कहना गलत है कि रूस किसी भी प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर रहा है। उन्होंने बताया कि मॉस्को में शुरुआती बैठकों के दौरान कुछ प्रस्ताव सामने रखे गए थे और उनसे कुछ समझौते करने को कहा गया था। एंकरिज पहुंचने पर उन्होंने साफ किया था कि ये फैसले रूस के लिए आसान नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए गए।

पुतिन के इस बयान को रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में एक अहम संकेत के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अब भी दोनों पक्षों के बीच ठोस सहमति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर स्पष्टता जरूरी मानी जा रही है।

सुरक्षा : समुद्र में भारत को मिली नई ताकत,तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल हुआ जहाज 'अमूल्य'

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारतीय तटरक्षक बल की समुद्री क्षमताओं को और मजबूती देते हुए आधुनिक फास्ट पेट्रोल वेसल 'अमूल्य' को शुक्रवार को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल कर लिया गया। एडम्या श्रेणी का यह तीसरा जहाज निगरानी, खोज और बचाव अभियान, समुद्री तस्करी पर अंकुश लगाने, अवैध गतिविधियों की रोकथाम और समुद्री प्रदूषण से निपटने जैसे अहम कार्यों में तैनात किया जाएगा। इसके शामिल होने से भारत के पूर्वी तट की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होने की उम्मीद है। तटरक्षक बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 'अमूल्य' समुद्र को सुरक्षित, स्वच्छ और संरक्षित रखने के प्रति बल की प्रतिबद्धता और मजबूत इच्छाशक्ति का प्रतीक है।

यह 51 मीटर लंबा फास्ट पेट्रोल जहाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में डिजाइन और निर्मित किया गया है। खास बात यह है कि इसमें 60 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी उपकरणों का उपयोग किया गया है, जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत, 'मेक इन इंडिया' और स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, इस तरह के जहाज न केवल सुरक्षा जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि घरेलू रक्षा उद्योग को भी नई मजबूती प्रदान करते हैं।

तकनीकी क्षमताओं की बात करें तो 'अमूल्य' में दो अत्याधुनिक 3000 किलोवाट के डीजल इंजन लगाए गए हैं, जिनकी मदद से यह जहाज 27 नॉट्स की अधिकतम रफ्तार हासिल कर सकता है। यह एक बार में लगभग 1500 समुद्री मील की दूरी तय करने में सक्षम है, जिससे लंबे समय तक समुद्र में गश्त और मिशन संचालन संभव हो पाता है। हथियार प्रणाली के रूप में जहाज में 30 मिमी की तोप और 12.7 मिमी की दो रिमोट कंट्रोल गन लगाई गई हैं। इसके साथ ही आधुनिक लक्ष्य पहचान और फायर कंट्रोल सिस्टम भी मौजूद हैं, जो किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं।

इसके अलावा, 'अमूल्य' में इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, मशीनरी कंट्रोल सिस्टम और ऑटोमैटिक पावर मैनेजमेंट सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं भी शामिल हैं। ये प्रणालियां जहाज की कार्यक्षमता, संचालन की सटीकता और सुरक्षा को कई गुना बढ़ा देती हैं, जिससे चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों में भी मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके। तटरक्षक बल के अनुसार, आईसीजीएस 'अमूल्य' को ओडिशा के पारादीप में तैनात किया जाएगा और यह उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कमांडर के अधीन कार्य करेगा। जहाज की कमान कमांडेंट (जूनियर ग्रेड) अनुपम सिंह के हाथों में होगी, जबकि इसमें 5 अधिकारी और 34 जवानों का प्रशिक्षित दल तैनात रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि 'अमूल्य' के शामिल होने से तटीय सुरक्षा, समुद्री निगरानी और आपदा के समय राहत एवं बचाव अभियानों में तटरक्षक बल की भूमिका और अधिक प्रभावी होगी। कुल मिलाकर, यह जहाज देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में एक नई ताकत बनकर उभरेगा।

संपादकीय

ग्रामीण क्षेत्रों में सफलता से जगी उम्मीदें

आम तौर पर आम आदमी पार्टी को शहरी जनाधार वाली पार्टी के रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन हालिया ग्रामीण निकाय चुनावों में उसकी जीत ने राजनीतिक विश्लेषकों को खूब चौंकाया है। पंजाब के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के परिणामों ने राजनीतिक वर्चस्व और उभरते मतभेदों की कहानी भी बयां की है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी यानी आप ने ग्रामीण निकाय चुनावों में शानदार सफलता को दर्ज करते हुए राज्यभर में बड़ी संख्या में सीटें जीती हैं। जिसने इस बात की पुष्टि की है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के शहरों में ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी लोकप्रियता का आधार रखती है। वहीं दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रामीण मतदाताओं में पंजाब की सत्ता में लंबे समय तक भागीदारी निभाने वाले राजनीतिक दलों से मोहभंग का सिलसिला लगातार बना हुआ है। हालांकि, आप की इस सफलता के साथ कुछ ऐसे पहलू भी जुड़े हैं, जिन पर पार्टी और उसके नेताओं को गहन विचार करने की जरूरत होगी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी का मजबूत प्रदर्शन उसके शासन के मॉडल के लिये निरंतर समर्थन का संकेत दे रहा है। यह एक ऐसा परिणाम है जो साल 2027 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में आप के पक्ष में सकारात्मक परिदृश्य बना सकता है। इसके विपरीत विरोधाभास यह भी है कि कई जगह ऐसे उल्लेखनीय उदाहरण सामने आए हैं, जहां आम आदमी पार्टी अपने नेताओं के गढ़ों में लड़खड़ा गई है। आप के कई प्रमुख नेता अपने ही गांवों में जीत हासिल करने में विफल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, आप को इस पर मंथन करने की जरूरत है। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने बठिंडा और मुक्तसर जैसे कुछ इलाकों में अपनी मजबूत पकड़ दर्शायी है। जो पार्टी के लिये हौसला बढ़ाने वाले संकेत कहे जा सकते हैं।

दरअसल, शिअद के प्रदर्शन को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी यदि इस बढ़त को आगे भी कायम रख पाती है तो उसके संगठनात्मक पुनरुद्धार के लिये दीर्घकालिक परिणाम सामने आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का चुनावी प्रदर्शन निराशाजनक ही कहा जाएगा। दरअसल, अब भी कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने लिये संघर्ष करती प्रतीत हुई है। ये कांग्रेस के लिये चिंता की ही बात हो सकती है कि वह अपने पारंपरिक गढ़ों तक में अब भी कोई ठोस व दमदार चुनौती पेश करने में असफल ही रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ बनानी आरंभ की है। हालांकि, उसकी यह बढ़त सिर्फ मामूली ही कही जाएगी। बहरहाल, कह सकते हैं कि चुनाव परिणामों से उपजी तसवीर पंजाब में बदलते राजनीतिक परिदृश्य की ओर ही इशारा करती नजर आती है। वैसे एक हकीकत यह भी है कि किसी भी चुनाव के परिणाम चुनावी परिदृश्य का आंशिक दृष्टिकोण ही परिभाषित करते हैं। मतदाता जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी की नीतियों से काफी हद तक संतुष्ट ही दिखे हैं। इसके बावजूद स्थानीय निष्ठाएं और उम्मीदवार विशिष्ट कारक प्रमुखता से सामने आते हैं। इन स्थानीय ग्रामीण इकाइयों के चुनावों में आम आदमी पार्टी के नेताओं के गृह क्षेत्रों में मिली हार इस बात की भी याद दिलाती है कि किसी दल के लिये राजनीतिक पूंजी बेहद नाजुक ही होती है। यह भी कि ग्रामीण मतदाता स्थानीय नेतृत्व के प्रति उतने ही सजग और संवेदनशील होते हैं, जितना कि राज्य स्तरीय विचारों के प्रति। आगे चलकर, अगर आप को पंजाब में अपने जनादेश को बनाये रखना है और साथ ही उसका विस्तार करना चाहती है, तो उसे जमीनी स्तर पर नेतृत्व को मजबूत प्राथमिकता के आधार पर तैयार करना होगा। साथ ही उसे ग्रामीण मतदाताओं की विभिन्न चिंताओं का समाधान भी प्राथमिकता के आधार पर करना होगा। अब ये आने वाला समय बताएगा कि आप ने इन चुनाव परिणामों के निहितार्थों का किस सीमा तक चिंतन-मनन किया है। यदि पार्टी इन चुनाव परिणामों से सबक लेकर अपनी रीतियों-नीतियों में बदलाव लाती है तो साल 2027 के विधानसभा चुनावों में उसका जनाधार मजबूत हो सकता है।

नाभिकीय ऊर्जा में निजी क्षेत्र का रास्ता खुला

> “भारत में परमाणु बिजली बनाने का काम अभी तक सरकारी कंपनी न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करती है। अब नाभिकीय बिजली उत्पादन में निजी क्षेत्र का प्रवेश भी होगा, जिसमें विदेशी कंपनियों की भागीदारी भी हो सकती है। यह घोषणा नाभिकीय ऊर्जा के मामले में भारत-अमेरिका संवाद फिर से कायम होने की ओर इशारा कर रही है।

संसद ने ‘सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विधेयक, 2025’ को पारित कर दिया। इसे अंग्रेजी नामाक्षरों के आधार पर ‘शांति-विधेयक’ कहा गया है। हालांकि, कई विपक्षी सांसदों ने विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की थी, पर सरकार ने इसे राज्यसभा में चर्चा के लिए भेजकर जल्दी पास कराना उचित समझा। अब यह कानून बन जाएगा। दोनों सदनों की राजनीतिक बहसों पर ध्यान नहीं दें, तो यह स्पष्ट है कि यह कानून यूपीए सरकार में अमेरिका के साथ हुई ‘न्यूक्लियर-डील’ का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो अब अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौते के साथ भी जुड़ा है।

यह कानून अनायास ही नहीं बनाया गया है। कई कारणों से ‘न्यूक्लियर डील’ अपने अभीप्सित उद्देश्यों में पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। एक बड़ा अड़ंगा, संभावित दुर्घटना की क्षतिपूर्ति को लेकर था, जिसके लिए 2010 में पास हुए नागरिक दायित्व अधिनियम से विदेशी आपूर्तिकर्ता सहमत नहीं थे। 2008 में, भाजपा ने मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसका एक कारण यह भी था कि ‘न्यूक्लियर डील’ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिससे क्षतिपूर्ति हो सके।

इस साल का बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने नाभिकीय ऊर्जा को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं की थीं। उन्होंने स्वदेशी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये के ‘परमाणु ऊर्जा मिशन’ की घोषणा की थी। 2033 तक इनमें से कम से कम पांच रिएक्टर चालू हो जाएंगे। भारत के 2047 तक 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा सुनिश्चित करने के बड़े लक्ष्य के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है।

उसके पहले पिछले साल जुलाई में नई सरकार

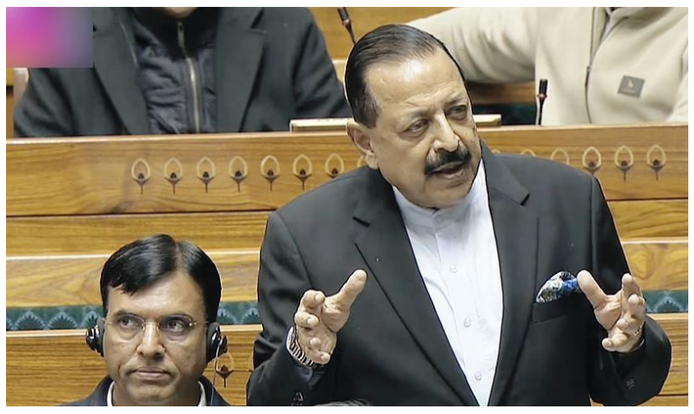

के पहले बजट भाषण में उन्होंने कहा था कि सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर (बीएसआर) की स्थापना, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (बीएसएमआर) के अनुसंधान और विकास, तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी।

भारत में परमाणु बिजली बनाने का काम अभी तक सरकारी कंपनी न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करती है। अब नाभिकीय बिजली उत्पादन में निजी क्षेत्र का प्रवेश भी होगा, जिसमें विदेशी कंपनियों की भागीदारी भी हो सकती है। यह घोषणा नाभिकीय ऊर्जा के मामले में भारत-अमेरिका संवाद फिर से कायम होने की ओर इशारा कर रही है। 2008 की न्यूक्लियर डील ने भारत और अमेरिका को काफी करीब कर दिया था, पर इसी डील ने दोनों के बीच खटास भी पैदा की थी।

न्यूक्लियर डील होते वक्त लगता था कि भारत नाभिकीय ऊर्जा के लिए अपने दरवाज़े खोलेगा, पर उस दिशा में प्रगति नहीं हुई, बल्कि सब कुछ धीमा पड़ गया। 2011 में जापान के फुकुशिमा एटमी बिजलीघर की दुर्घटना के बाद उससे जुड़े जोखिम को लेकर भी सवाल उठे। भारतीय संसद ने 2010 में सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट पास किया, जिसमें वे व्यवस्थाएं थीं, जो परमाणु दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे का भार उपकरण सप्लाई करने वाली कंपनी पर डालती थीं।

उस कानून की धारा 17 से जुड़े मसले पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं रही है। यह असहमति केवल अमेरिका के साथ ही नहीं थी, दूसरे देशों के साथ भी थी। 2010 में जब यह कानून पास हो रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी भी कड़ी शर्तें लागू करने की पक्षधर थी। बाद में यूपीए सरकार पर जब अमेरिकी दबाव पड़ा तो रास्ते खोजे जाने लगे।

भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 1.5 प्रतिशत और उत्पादित बिजली का 3 प्रतिशत हिस्सा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से आता है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने, ग्रिड की स्थिरता में सुधार करने और 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हाल के वर्षों में सरकार के एजेंडे में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण करना प्रमुख रहा है।

भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास विधेयक, 2025, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, पुराने 1962 के कानून और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 दोनों को निरस्त करके उनका स्थान लेगा। वर्ष 1962 का कानून परमाणु ऊर्जा के विकास और उपयोग के आधार प्रदान करता है, और 2010 का परमाणु दुर्घटना के मामले में दायित्व और मुआवजा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। नया कानून दो स्पष्ट जरूरतों से प्रेरित है। एक, कोयले पर आधारित ऊर्जा के स्थान पर अक्षय ऊर्जा क्षमता का निर्माण और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, नाभिकीय-क्षमता वृद्धि के लिए पूंजी की आवश्यकता।

वर्ष 1962 के अधिनियम के तहत परमाणु ऊर्जा से जुड़ी गतिविधियों के लिए लाइसेंस केवल केंद्र सरकार की इकाई या सरकारी कंपनियों को ही दिया जा सकता है। वहीं नाभिकीय दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति के लिए 2010 के अधिनियम के तहत, परमाणु स्थापना का संचालक ‘नो-फॉल्ट’ सिद्धांत के अनुसार परमाणु घटना के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी है। ऑपरेटरों को देनदारियों को कवर करने के लिए बीमा रखना होगा। ऑपरेटर की देयता की अधिकतम सीमा भी तय है, जिसके ऊपर की देयता केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। 2010 के अधिनियम में 10 मेगावाट या उससे अधिक की ताप विद्युत क्षमता वाले परमाणु रिएक्टर के लिए अधिकतम 1,500 करोड़ रुपये की देनदारी निर्दिष्ट की गई थी। अब नए कानून में क्षमता के आधार पर 100 करोड़ रुपये से 3,000 करोड़ रुपये तक की देयता सीमा तय की गई है। इस सीमा के ऊपर की क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार करेगी। लोकहित में जरूरी हुआ, तो वह किसी गैर-सरकारी संस्था का पूरा दायित्व भी अपने ऊपर ले सकती है।

अब सरकारी संस्थाओं, संयुक्त उपक्रमों और ‘अन्य किसी कंपनी’ को लाइसेंस के जरिए नाभिकीय ऊर्जा गतिविधियों की अनुमति देने की इजाजत देकर, संसद ने संकेत दिया है कि घरेलू निजी पूंजी इन्हें चलाए, न कि विदेशी संयंत्र मालिक। 100 गीगावॉट का लक्ष्य पूरा करने के लिए भारत को बड़े पैमाने पर पूंजी जुटानी होगी। निर्माण संबंधी जोखिम साझा कर सकने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं को भी खोजना होगा। साथ ही नाभिकीय प्रसार के लिहाज से संवेदनशील कामों को राज्य के मातहत रखना होगा। इस कानून में सेफ्टी, क्रियान्वयन और विवाद-समाधान तथा भागीदारी की शर्तों को एक साथ समेटने का प्रयास किया गया है।

पश्चिम एशिया के कुछ सरकारी कोषों और विदेशी निधियों ने आंशिक वित्तपोषण में रुचि दिखाई है, जिसमें एसएमआर की विनिर्माण शृंखला में प्रवेश करना भी शामिल है। परमाणु ऊर्जा को व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी विकल्प बनाए रखने के लिए एसएमआर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सरकारी सूत्रों ने संकेत दिया है कि नाभिकीय क्षेत्र में इक्विटी निवेश के नियम सरकार के विदेशी इक्विटी भागीदारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगे।

दो प्रमुख संशोधन खासतौर से महत्वपूर्ण हैं। एक का उद्देश्य एक विशिष्ट प्रावधान-नागरिक दायित्व कानून की धारा 17 (बी) को कमज़ोर करना है, जिसे दुनियाभर में लागू किए गए इसी तरह के परमाणु दायित्व कानूनों के विपरीत माना गया था। इसे विदेशी उपकरण विक्रेताओं ने बाधा बताया है। इस धार पर किसी ने भी कानून लागू होने के बाद से भारत में किसी भी परियोजना में निवेश नहीं किया है। यह भारतीय उप-विक्रेताओं के लिए भी चिंता का विषय था, क्योंकि ‘आपूर्तिकर्ता’ शब्द का दायरा बहुत व्यापक माना जाता है। अब इसे भी स्पष्ट किया गया है।

प्रेरणा

प्रतिबद्धता की मशाल: जब पत्रकारिता ने सत्ता को नहीं, सत्य को चुना

पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम नहीं होती, वह समाज की अंतरात्मा होती है। जब यह अंतरात्मा सत्ता के दबाव में झुक जाती है, तो शब्द खोखले हो जाते हैं और जब वही पत्रकारिता सत्य, स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना के प्रति प्रतिबद्ध रहती है, तब वह इतिहास रचती है। पं. बनारसीदास चतुर्वेदी जी का जीवन इसी प्रतिबद्धता की ऐसी ही जीवंत मिसाल है, जिसमें सिद्धांत सुविधा पर और सत्य सत्ता पर भारी पड़ा। एक बार उनके पास एक राजसी संदेश आया। आदेश नहीं, बल्कि आग्रह के रूप में कहा गया कि अमुक-अमुक स्थानों पर लगाई गई प्याऊओं का विस्तृत विवरण ‘मधुकर’ पत्रिका में प्रकाशित किया जाए। देखने में यह एक सामान्य सामाजिक कार्य का प्रचार लग सकता था, लेकिन चतुर्वेदी जी की दृष्टि उससे कहीं आगे तक जाती थी। वे समझ गए थे कि यह पत्रकारिता के माध्यम से दरबारी प्रशंसा का बीज बोने का प्रयास है। उन्होंने बिना किसी हिचक के साफ शब्दों में मना कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ओरछा नरेश को संदेश भिजवाकर यह भी कह दिया कि यदि पत्रिका को इसी दिशा में ले जाना है, तो वे उसका संपादन कार्य छोड़ देना ही उचित समझते हैं। यह निर्णय आसान नहीं था। सन 1930 में ओरछा नरेश वीरसिंह जू देव के प्रस्ताव पर वे टीकमगढ़ गए थे और ‘मधुकर’ नामक पत्र का संपादन आरंभ किया था। नरेश ने उन्हें पूर्ण संपादकीय स्वतंत्रता का आश्वासन दिया था। प्रारंभ में सब कुछ ठीक चला, लेकिन समय के साथ चतुर्वेदी जी ने महसूस किया कि राजा साहब ‘मधुकर’ को राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन की आवाज़ बनाने के बजाय एक सीमित दरबारी पत्र के रूप में देखना चाहते हैं। यह वही क्षण था, जहाँ पत्रकारिता की असली परीक्षा होती है। अधिकांश लोग समझौते का रास्ता चुनते हैं, लेकिन चतुर्वेदी जी ने त्याग का मार्ग अपनाया।

उन्होंने सत्ता की निकटता, सुविधा और प्रतिष्ठा को ठुकराकर सिद्धांतों की रक्षा की। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ था समाज के लिए लिखना, देश के लिए सोचना और सत्य के लिए खड़ा होना। यही कारण था कि वे केवल एक संपादक नहीं, बल्कि विचारों के प्रहरी थे। उनके लेखों में स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना, सामाजिक सुधार की पीड़ा और सांस्कृतिक स्वाभिमान की सुगंध स्पष्ट दिखाई देती थी।

पं. बनारसीदास चतुर्वेदी जी केवल पत्रकार ही नहीं थे, वे एक समर्पित साहित्यसेवी भी थे। उनका जीवन लेखन, संवाद और विचार-विनिमय से भरा हुआ था। वे प्रतिदिन दर्जनों पत्र लिखा करते थे। यह पत्र केवल औपचारिक संवाद नहीं थे, बल्कि विचारों का प्रवाह थे। देश-विदेश की अनेक विभूतियों को लिखे गए उनके पत्र आज भी पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं और उस युग की बौद्धिक चेतना के साक्ष्य हैं। उनके पत्रों से पता चलता है कि वे कितनी गहराई से समाज, राजनीति, साहित्य और संस्कृति पर विचार करते थे।

स्वतंत्रता के बाद भी उनका सार्वजनिक जीवन सक्रिय रहा। भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात वे बारह वर्षों तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। संसद के उच्च सदन में रहते हुए भी उन्होंने कभी सत्ता की भाषा नहीं बोली, बल्कि विवेक और विवेचना की आवाज़ बने रहे। उनके विचारों में संतुलन था, भाषा में शालीनता थी और दृष्टि में राष्ट्रहित सर्वोपरि था। यही कारण था कि वे सभी दलों और विचारधाराओं में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते थे।

उनका योगदान केवल लेखन या राजनीति तक सीमित नहीं रहा। ‘विशाल भारत’ नामक हिन्दी मासिक के संपादक के रूप में उन्होंने हिन्दी पत्रकारिता को वैचारिक गहराई दी। साक्षात्कार की विधा को पुष्पित और पल्लवित करने में उनका विशेष योगदान रहा। उन्होंने साक्षात्कार को केवल प्रश्नोत्तर तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे विचारों के संवाद का माध्यम बनाया। उनके द्वारा लिए गए साक्षात्कार आज भी पठनीय और विचारोत्तेजक माने जाते हैं।

सन 1973 में उन्हें पद्मभूषण से सम्मानित किया गया। यह सम्मान केवल उनके साहित्यिक और पत्रकारिता योगदान का नहीं था, बल्कि उस नैतिक साहस का भी था, जिसने उन्हें सत्ता के सामने झुकने से रोका। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची पत्रकारिता वही है, जो प्रतिबद्ध हो—सत्य के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति।

आज जब पत्रकारिता पर प्रश्नचिह्न लगाए जाते हैं, तब पं. बनारसीदास चतुर्वेदी जी जैसे व्यक्तित्व हमें याद दिलाते हैं कि कलम की ताकत पद से नहीं, बल्कि चरित्र से आती है। उनकी प्रतिबद्धता आज भी एक मशाल की तरह जल रही है, जो यह रास्ता दिखाती है कि पत्रकारिता यदि अपने मूल्यों पर अडिग रहे, तो वह केवल खबर नहीं बनाती, इतिहास भी रचती है।

राहुल की सीमाएं, प्रियंका की संभावनाएं

वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर संसद में हुई चर्चा में दो भाषणों की बड़ी चर्चा हुई। एक प्रधानमंत्री मोदी का, जिन्होंने कांग्रेस पर तीखे हमले किए। दूसरा, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का। प्रियंका ने मोदी और भाजपा को निशाने पर रखा, पर उसका असर कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में भी दिखने लगा है।

सदन के नेता के नाते प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम् पर चर्चा की शुरूआत की। अपेक्षित तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से था, पर कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाला प्रियंका ने। ऐसा क्यों हुआ, यह तो कांग्रेस ही बता सकती है, पर मोदी की भाषण कला की प्रशंसा करते हुए भी प्रियंका हास-परिहास के बीच ही तर्कों और तथ्यों के साथ सत्तापक्ष पर कटाक्षों से सदन को प्रभावित करने में सफल दिखीं।

राहुल गांधी भी बोले, मगर चुनाव सुधार पर चर्चा में। उन्होंने मुख्यतः वोट चोरी के आरोप दोहराए, जो वह पहले लगाते रहे हैं। उनके भाषण में न तो नए तथ्य-तर्क दिखे और न ही प्रियंका की तरह आक्रामक हुए बिना सत्तापक्ष को कठघरे में खड़ा करने की कला।

राहुल वोट चोरी के पुराने आरोप दोहरा भर रहे थे, जबकि प्रियंका वंदे मातरम् विवाद के सभी पहलुओं पर तैयारी करके आई थीं। तथ्यों और तर्कों के साथ अपनी बात कहना ही संसदीय चर्चा की प्रभावी शैली है। प्रियंका ने इसी प्रभावी शैली का परिचय दिया। शायद इसलिए भी खुद कांग्रेस के अंदर राहुल से तुलना करते हुए प्रियंका को बड़ी राजनीतिक भूमिका देने की चर्चा फिर जोर पकड़ने लगी है।

ओडिशा के पूर्व विधायक मोहम्मद मोक्विम ने उम्र के हवाले से मल्लिकार्जुन खरगे को हटाकर प्रियंका गांधी को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाने की मांग की। उन्होंने राहुल गांधी पर भी अप्रत्यक्ष निशाना साधा। कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित कर दिया। टीम राहुल और टीम प्रियंका में कथित टकराव की चर्चाओं को भाजपा द्वारा हवा देने के राजनीतिक निहितार्थ खोजे जा सकते हैं, पर इससे इनकार नहीं कि दोनों की अपनी-अपनी टीम है और देश-प्रदेश में अपने-अपने पसंदीदा नेता भी।

कई प्रसंग बताते हैं कि राहुल और प्रियंका, कांग्रेस में दो सत्ता केंद्र बन गए हैं। माना जाता है कि राहुल को उत्तराधिकारी बनाने तथा पार्टी में दो सत्ता केंद्रों से बचने के मकसद से ही सोनिया ने प्रियंका को परदे के पीछे की भूमिका में रखा। सोनिया और राहुल के चुनाव क्षेत्रों में प्रचार और प्रबंधन संभालती रहीं प्रियंका को राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी बनने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा।

बेशक ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ के नारे के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ज्यादा महिला उम्मीदवारों पर प्रियंका का दांव नहीं चला। इसके बावजूद पिछले साल रायबरेली से भी निर्वाचित राहुल द्वारा खाली की गई वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव में प्रियंका को उम्मीदवार बनाने से उनकी भी जरूरत का संकेत गया। अर्थ निकाला गया कि प्रियंका अपेक्षाकृत अनुकूल दक्षिण भारत में कांग्रेस संभालेंगी, जबकि अध्यक्ष पद से पहले ही मुक्त हो चुके राहुल शेष देश में भाजपा से मोर्चा लेंगे, लेकिन वांछित परिणाम दिखे नहीं।

लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद कांग्रेस हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई। विपक्षी गठबंधन में सहयोगी दलों के साथ भी कांग्रेस के रिश्ते सहज नहीं हैं। तीन लोकसभा और अनेक विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद संगठन कांग्रेस की प्राथमिकताओं में नजर नहीं आता। खरगे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पर अहम् फैसले राहुल ही ले रहे हैं। हरियाणा में पिछले नेता प्रतिपक्ष को ही पुनः चुनने में लगभग पूरा साल लग गया। दरअसल मां सोनिया की कांग्रेस को राहुल अपना नहीं पा रहे और अपनी पसंद की कांग्रेस बनाने का साहस जुटा नहीं पा रहे, जिसका परिणाम नेताओं के पलायन के रूप में भी सामने आ रहा है।

पदयात्रा से राहुल की छवि बेहतर हुई थी, लेकिन संगठनात्मक कमजोरी के चलते उसका ज्यादा चुनावी लाभ मिला नहीं। राहुल की छवि मोदी पर तल्ख हमले करते हुए टकराव की राजनीति करने वाले नेता की बन गई है। उनकी राजनीति और मुद्दों में निरंतरता का अभाव भी है। लोकसभा चुनाव तक ईवीएम पर निशाना साधते हुए संविधान और आरक्षण को खतरा मुद्दा था तो अब वोट चोरी का नारा बुलंद किया जा रहा है।

बीच-बीच में राहुल जिस तरह विदेश चले जाते हैं, उससे भाजपा को उनकी अगंभीर राजनेता की छवि बनाने का मौका मिलता है। राज्यों के वरिष्ठ नेताओं के लिए भी राहुल से मुलाकात आसान नहीं। इसका असर कांग्रेसियों में पार्टी और अपने भविष्य की चिंता के रूप में सामने आ रहा है। प्रियंका गांधी में उन्हें बेहतर संभावनाएं दिखती हैं।

इंदिरा गांधी की झलक के अलावा राजनीतिक समझ, संवाद और प्रभावी भाषण शैली में प्रियंका, राहुल से बेहतर मानी जाती हैं। इसलिए भी वंदे मातरम् पर संसद में प्रभावशाली भाषण के बाद उन्हें बड़ी राजनीतिक भूमिका की चर्चा जोर पकड़ रही है। प्रियंका का एक ही नकारात्मक पहलू है-पति राबर्ट वाड्रा के विरुद्ध दर्ज मुकदमे। अध्यक्ष के रूप में खरगे का कार्यकाल 2027 तक है। जाहिर है, प्रियंका की किसी भी नई भूमिका का फैसला सोनिया ही करेंगी, लेकिन वह कब और क्या होगी, यह देखना दिलचस्प होगा।

अभियान

माँ के नामों में छिपी जीवन-शक्ति: जब दुर्गा के 108 नाम साधक का पथ बदल देते हैं

सनातन परंपरा में कहा गया है कि संसार की हर गति शक्ति से चलती है और उस शक्ति का सबसे करुण, सबसे रक्षक और सबसे जाग्रत स्वरूप माँ दुर्गा हैं। जब मनुष्य जीवन में बार-बार ठोकर खाता है, जब प्रयास के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, जब भीतर भय, ग्लानि और असहायता घर करने लगती है, तब माँ दुर्गा का स्मरण केवल धार्मिक कर्म नहीं रह जाता, वह जीवन का सहारा बन जाता है। माँ के 108 नामों की साधना इसी सहारे को धीरे-धीरे आंतरिक बल में बदल देती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर में एक साधारण गृहस्थ रहता था। जीवन में न कोई बड़ा पद था, न विशेष विद्या, लेकिन जिम्मेदारियाँ बहुत थीं। व्यापार में हानि, घर में बीमारी और मन में निरंतर चिंता ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। वह रोज़ मंदिर जाता, लेकिन मन शांत नहीं होता। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उसे माँ दुर्गा के 108 नामों का स्मरण करने की सलाह दी। उसने कहा कि इन नामों को माँ से कुछ माँगने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को माँ के चरणों में रखने के लिए जपो। उस व्यक्ति ने बिना किसी विशेष विधि-विधान के, केवल श्रद्धा के साथ रोज़ सुबह-शाम माँ के नाम लेने शुरू किए। समय के साथ उसके जीवन की परिस्थितियाँ अचानक नहीं बदलीं, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदलने लगा। जहाँ पहले वह हर समस्या में टूट जाता था, वहीं अब वह धैर्य से काम लेने लगा। उसे यह अनुभव होने लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संभाल रही है। धीरे-धीरे व्यापार में सुधार हुआ, घर का वातावरण शांत हुआ और सबसे बड़ी बात यह हुई कि उसका भय समाप्त होने लगा। उसने समझा कि माँ दुर्गा के नाम केवल बाहरी संकटों को नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार को भी दूर करते हैं।

श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का उल्लेख दुर्गा सप्तशती में मिलता है। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान शिव ने स्वयं माँ दुर्गा की स्तुति इन 108 नामों के माध्यम से की थी। प्रत्येक नाम माँ के किसी न किसी गुण को प्रकट करता है। कोई नाम माँ को रक्षक के रूप में दर्शाता है, कोई संहारक के रूप में, कोई पालनकर्ता के रूप में और कोई ज्ञान देने वाली शक्ति के रूप में। जब साधक इन नामों का जप करता है, तो वह जीवन के हर स्तर पर माँ की ऊर्जा को आमंत्रित करता है।

कहा जाता है कि इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से जीव जीवनमुक्त होने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार से विरक्ति आ जाए,

बल्कि यह कि संसार में रहते हुए मन बंधनों से मुक्त होने लगे। माँ दुर्गा की साधना व्यक्ति को कर्तव्य से भागना नहीं सिखाती, बल्कि कर्तव्य निभाने की शक्ति देती है। यही कारण है कि गृहस्थ हों या संन्यासी, सभी के लिए यह स्तोत्र समान रूप से फलदायी माना गया है।

जप की विधि भी सरल है, लेकिन उसका भाव गहरा होना चाहिए। प्रातःकाल या रात्रि के शांत समय में, मन को स्थिर कर माँ का ध्यान किया जाता है। दीपक की लौ में माँ के स्वरूप की कल्पना की जाती है और फिर एक-एक नाम को श्रद्धा के साथ उच्चारित किया जाता है। जप करते समय मन में यह भाव रखा जाता है कि माँ सब देख रही हैं, सब जानती हैं और सब संभाल रही हैं। धीरे-धीरे साधक को यह अनुभव होने लगता है कि माँ केवल बाहर नहीं, उसके भीतर भी विराजमान हैं।

नवरात्रि में इस साधना का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन वास्तव में माँ की कृपा किसी काल-सीमा में बंधी नहीं होती। जो व्यक्ति निष्ठा से माँ के नामों का स्मरण करता है, उसके जीवन में अदृश्य परिवर्तन होने लगते हैं। कई बार साधक यह भी अनुभव करता है कि कुछ इच्छाएँ पूरी नहीं हुईं, लेकिन बाद में वही अधूरी इच्छाएँ उसके लिए वरदान सिद्ध होती हैं। तब उसे समझ में आता है कि माँ ने वही किया, जो उसके लिए श्रेष्ठ था।

माँ दुर्गा के 108 नामों का जप व्यक्ति के भीतर विनम्रता लाता है। अहंकार धीरे-धीरे पिघलने लगता है और उसके स्थान पर विश्वास जन्म लेता है। यह विश्वास ही साधना का वास्तविक फल है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि वह अकेला नहीं है और एक दिव्य शक्ति हर कदम पर उसके साथ है, तब जीवन की कठिनाइयाँ भी बोझ नहीं लगतीं। अंततः माँ दुर्गा के 108 नाम कोई साधारण स्तोत्र नहीं हैं। वे जीवन को समझने, स्वीकार करने और सँवारने का मार्ग हैं। जो व्यक्ति इन नामों के साथ जीवन को जोड़ लेता है, उसके लिए चमत्कार किसी एक दिन की घटना नहीं रहते, बल्कि हर दिन एक शांत, संतुलित और जाग्रत जीवन का अनुभव बन जाते हैं। यही माँ दुर्गा की कृपा का सबसे सुंदर रूप है, यही इस साधना का सच्चा सार है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

अटल नेतृत्व, अविरत विकास

गुजरात में राजस्व सुधारों से राज्य के नागरिकों को तेज एवं पारदर्शी सेवा सुनिश्चित हुई

▸▸ भूमि पंजीकरण से लेकर गैर कृषि भूमि की मंजूरी तक की प्रक्रियाएँ सरल, पारदर्शी तथा डिजिटल बनने से गुजरात सुशासन का रोल मॉडल बना

▸▸ iORA पोर्टल पर पिछले तीन वर्षों में 17.9 लाख से अधिक आवेदन प्रोसेस किए गए, फीडबैक सेंटर द्वारा 40 हजार से अधिक कॉल द्वारा रिस्पॉन्स प्राप्त किए गए

▸▸ गतिशक्ति पोर्टल के साथ एकीकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण तथा किसानों को मुआवजे की प्रक्रिया तेज बनी

(जीएनएस)। गांधीनगर : राज्य के नागरिकों तक प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जरूरी राजस्व सुधार कर सुशासन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनका नेतृत्व पारदर्शिता, सरलता तथा टेक्नोलॉजी आधारित प्रशासन के लिए विख्यात है। इसी कारण गुजरात सरकार द्वारा लागू किए गए व्यापक सुधार आज राज्य के किसानों, उद्योगों तथा विकास परियोजनाओं के लिए वरदानस्वरूप सिद्ध हुए हैं। भूमि पंजीकरण से लेकर गैर कृषि (एनए) भूमि की मंजूरी तक की प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी एवं डिजिटल बनाए जाने से गुजरात सुशासन का रोल मॉडल बना है। इन सुधारों के कारण राज्य के विकास को नई गति मिली है, जो 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' तथा 'ईज ऑफ लिविंग' को मजबूती देती है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग ने एंड-टू-एंड डिजिटल गवर्नेंस को नई गति दी है। ई-धरा जैसे सिस्टम्स को अधिक मजबूत बनाया गया है, जिसके कारण सत्यापनयुक्त भूमि रिकॉर्ड सुरक्षित एवं तेजी से नागरिकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप भूमि संबंधी विवादों में उल्लेखनीय कमी आई है। कानूनी सुरक्षा बनाए रखते हुए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गैर कृषि (एनए) भूमि मंजूरी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन बनाई गई है। इसमें समय पर मंजूरी मिलने से समय एवं खर्च में कमी आई है और उद्योगों को फायदा होने के साथ किसानों के हित का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ; डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम अंतर्गत 34 जिलों में भूमि मापन तथा रीसर्वे के कार्य के कारण भूमि विवादों में कमी आई है और किसानों को ऋण, फसल बीमा तथा सरकारी सहायता आसानी से मिल रहे हैं।

iORA पोर्टल पर 17.9 लाख से अधिक आवेदन प्रोसेस किए गए

भूमि आवंटन से जुड़े सुधारों के अंतर्गत iORA पोर्टल द्वारा राज्य के नागरिकों तक तेज एवं पारदर्शी सेवाएँ पहुँचाने में सरलता हुई है। 7/12 उतारो (लैंड रिकॉर्ड्स) के अलावा वंशानुगत रिकॉर्ड, गैर-कृषि की अनुमति तथा भूमि मापन जैसे 36 से भी अधिक राजस्व सेवाओं का लाभ iORA पोर्टल द्वारा घर बैठे लिया जा सकता है। वर्ष 2022 से 18 दिसंबर 2025 तक iORA पोर्टल पर विभिन्न प्रकार की 36 सेवाओं से जुड़े कुल 17.9 लाख से अधिक आवेदन प्रोसेस किए गए हैं। इस फेसलेस सर्विस के कारण सेवाओं में पारदर्शिता आई है और निर्णय प्रक्रिया तेज बनी है। iORA फीडबैक सेंटर पर लगभग 40799 कॉल के जवाब दिए गए हैं।

सेवाओं में डिजिटलाइजेशन तथा टेक्नोलॉजिकल सुधार

राजस्व सेवाओं में डिजिटल टेक्नोलॉजी को शामिल किए जाने से कामकाज अधिक आसान, पारदर्शी तथा तेज बना है। गरवी 2.0 पोर्टल के राज्यव्यापी क्रियान्वयन द्वारा दस्तावेज पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन एवं फेसलेस बनाई गई है। स्वामित्व योजना अंतर्गत ड्रोन फ्लाइट द्वारा 8700 से अधिक गाँवों में सर्वेक्षण पूर्ण कर 11.52 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण किया गया है। जन सेवा तथा ई-धरा केन्द्रों से फिजिकल हस्ताक्षर-मुहर आदि की डिजिटल हस्ताक्षर एवं क्यूआर कोड वाली प्रतियाँ (VF-6, VF-7, 8A) प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा; आवेदक अब सिटी सर्वे कार्यालय पर प्रत्यक्ष जाए बिना ऑनलाइन माध्यम से ई-सील प्रमाणित प्रॉपर्टी कार्ड की प्रति घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं।

अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से भूमि की मैपिंग, 3339 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की भूमि अतिक्रमणमुक्त की गई

राजस्व विभाग ने इसरो की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से राज्य के समग्र भूभाग की उच्च रिजॉल्यूशन क्षमता के साथ मैपिंग शुरू की है। इस पहल अंतर्गत सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमणों, लीज पर दी गई भूमि के दुरुपयोग तथा अनियंत्रित खनन जैसी गतिविधियों पर सटीक देखरेख रखी जाती है। एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तथा मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी द्वारा कोई भी अवैध फेरबदल होते ही iORA और RO Diary पर स्वचालित (ऑटोमैटिक) अलर्ट जनरेट होता है, जिससे भूमि पर त्वरित कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है। राज्य में सरकारी जमीनों के संरक्षण के लिए चलाए गए सघन अभियान द्वारा अब तक 3990 हेक्टेयर से अधिक भूमि अतिक्रमणमुक्त की गई है। पुनः प्राप्त की गई इस भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य 3339 करोड़ रुपए से अधिक है।

गतिशक्ति पोर्टल के साथ एकीकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण तथा किसानों को मुआवजे की प्रक्रिया तेज बनी

भूमि अधिग्रहण कार्य को तेज बनाने के लिए गतिशक्ति पोर्टल के साथ एकीकरण किया गया है, जिसके कारण राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग 60 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में भूमि अधिग्रहण किया गया है। इनमें बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेसवे, आबू रोड-तारंगा हिल रेलवे तथा केशोद एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में सफलतापूर्वक भूमि अधिग्रहण होने से किसानों को तेजी से मुआवजा मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा किए गए इन निर्णयों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प के अनुसार 'विकसित भारत@2047' के लिए विकसित गुजरात निर्माण की यात्रा अधिक वेगवान बनेगी। गुजरात में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से एक कदम आगे बढ़कर 'कम्फर्ट ऑफ डूइंग बिजनेस' तथा 'मैक्सिमम गवर्नेंस-मिनिमम गवर्नमेंट' चरितार्थ होंगे।

कांदिवली–बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के कार्य के संबंध में पश्चिम रेलवे का मेजर ब्लॉक

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली–बोरीवली सेक्शन पर छठी लाइन के कार्य को पूरा करने के लिए 30 दिनों का ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक 20/21 दिसंबर, 2025 की रात्रि से प्रारंभ होकर 18 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस कार्य में कांदिवली एवं बोरीवली स्टेशनों पर ट्रैक स्लीविंग तथा कई क्रॉसओवरों का इन्सर्शन एवं रिमूवल शामिल है। इसके अंतर्गत इंजीनियरिंग, सिगनलिंग तथा ओवरहेड इक्विपमेंट से जुड़े प्रमुख कार्य किए जाएंगे, जिससे रेल परिचालन प्रभावित होगा। परिणामस्वरूप कुछ उपनगरीय, पैसेंजर एवं मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित होंगी।

श्री विनीत ने आगे बताया कि इस अवधि के दौरान पाँचवीं लाइन पर यात्री ट्रेनों का परिचालन निलंबित रहेगा तथा अन्य

लाइनों पर गति प्रतिबंध लागू रहेंगे। पाँचवीं लाइन पर चलने वाली सभी मेल/एक्सप्रेस एवं उपनगरीय ट्रेनें अंधेरी/गोरेगांव और बोरीवली के बीच फास्ट लाइन पर चलाई जाएंगी। यह ब्लॉक 20/21 दिसंबर, 2025 से 25/26 दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान प्रतिदिन 23:00 बजे से 04:30 बजे तक लिया जाएगा।

ब्लॉक एवं पाँचवीं लाइन के निलंबन के कारण कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी, जिनका विवरण सभी उपनगरीय स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध रहेगा।

ब्लॉक के कारण प्रभावित ट्रेनों का विवरण संलग्न परिशिष्टों में दिया गया है:

परिशिष्ट–I: 20/21 दिसंबर, 2025 को तथा 21 से 25 दिसंबर, 2025 तक निरस्त ट्रेनें

परिशिष्ट–II: 26 दिसंबर, 2025 को निरस्त ट्रेनें

नोट: उपनगरीय लोकल ट्रेनों पर पड़ने वाले प्रभाव की सूचना यथासमय दी जाएगी। 31 दिसंबर, 2025 के लिए नववर्ष समारोह को ध्यान में रखते हुए असामान्य निरस्तीकरण न हों, इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

आणंद जिले के तारापुर के रिंझा में 110 करोड़ रुपए की लागत से साबरमती नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का तारापुर तहसील के चार गांवों के ग्रामीणों की वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी निवारण लाने वाला लोक हितकारी दृष्टिकोण

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आणंद जिले की तारापुर तहसील के रिंझा गांव में साबरमती नदी पर नए पुल के 110 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण को मंजूरी दी है। तारापुर तहसील के रिंझा, नभोई, पचेगाम और दुगारी गांवों के लोगों ने साबरमती नदी का बहाव बदल जाने के कारण बरसात के मौसम में नदी के उस पार पर नहीं जा पाने तथा संपर्क से वंचित हो जाने की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुति की थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस प्रस्तुति पर संवेदनापूर्ण प्रतिक्रिया देते हुए टू-लेन पुल ब्रिज सहित पथ रेखा पर 4 किलोमीटर का नया मार्ग बनाने हेतु भूमि अधिग्रहण,

निर्माण से पूर्व हाइड्रोलिक सर्वेक्षण, सॉइल इन्वेस्टिगेशन एवं आलेखन जैसी निर्माण पूर्व गतिविधियों सहित संभावित खर्च के लिए कुल मिलाकर 110 करोड़ रुपए आवंटित करने की अनुमति दी है। इस पुल का निर्माण पूर्ण होने से बरसात के दौरान नदी का बहाव बदल जाने से संपर्क विहीन हो जाने वाले इन गांवों की वर्षों पुरानी समस्या का निवारण हो जाएगा तथा परिवहन, कृषि-उद्योग और ईज ऑफ लिविंग के लिए यह पुल आशीर्वाद समान बनेगा।

पार्थ जिंदल बने सीमेंट निर्माता संघ के नए अध्यक्ष, डॉ. राघवपत सिंघानिया को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी

(जीएनएस)। मुंबई। भारत के सीमेंट उद्योग के शीर्ष संगठन सीमेंट निर्माता संघ (सीएमए) को नया नेतृत्व मिल गया है। 18 दिसंबर 2025 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पार्थ जिंदल को सर्वसम्मति से सीएमए का नया अध्यक्ष चुना गया। वहीं, जेके सीमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. राघवपत सिंघानिया को संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोनों नियुक्तियों को सीएमए के सभी सदस्यों का व्यापक समर्थन मिला, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उद्योग को उनके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। पार्थ जिंदल ने श्री सीमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नीरज अखौरी का स्थान लिया है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में संघ को स्थिरता और मजबूती प्रदान की थी।

सीमेंट निर्माता संघ के लगभग 60 वर्षों के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर युवा पीढ़ी के प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्थ जिंदल सीएमए के अब तक के सबसे कम उम्र के निर्वाचित अध्यक्ष बने हैं। इस बदलाव को उद्योग में पीढ़ीगत नेतृत्व परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे सीमेंट उद्योग को नई ऊर्जा, आधुनिक सोच और तेजी से बदलते वैश्विक व घरेलू परिदृश्य के अनुरूप निर्णय लेने की क्षमता मिलेगी। उद्योग जगत को उम्मीद है कि यह युवा नेतृत्व नवाचार और तकनीक आधारित समाधानों के जरिए सीमेंट सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत करेगा। अध्यक्ष पद संभालने के बाद पार्थ जिंदल से अपेक्षा की जा रही है कि वे नीति निर्माताओं, नियामकों और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ सीएमए की भूमिका को और प्रभावी बनाएंगे। विशेष रूप से सतत विनिर्माण, डीकार्बोनाइजेशन, ऊर्जा संक्रमण और लॉजिस्टिक्स के अनुकूलन जैसे अहम मुद्दों पर उनका फोकस रहने की संभावना है। भारत का सीमेंट उद्योग कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में जिंदल का नेतृत्व इस परिवर्तन को और गति दे सकता है।

पश्चिम रेलवे चलाएगी दो जोड़ी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी बढ़ती यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से मुंबई सेंट्रल – नई दिल्ली एवं बांद्रा टर्मिनस – अमृतसर स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर दो सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 04001/04002 मुंबई सेंट्रल – नई दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल [08 फेरे]

ट्रेन संख्या 04001 मुंबई सेंट्रल – नई दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल मुंबई सेंट्रल से 23:30 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 20:50 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। यह ट्रेन 21, 24, 27 एवं 30

दिसंबर, 2025 को चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04002 नई दिल्ली – मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल नई दिल्ली से 22:40 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 21:00 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन 20, 23, 26 एवं 29 दिसंबर, 2025 को चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी एवं मथुरा स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, एसी-3 टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 04695/04696 बांद्रा टर्मिनस – अमृतसर सुपरफास्ट स्पेशल [04 फेरे]

ट्रेन संख्या 04695 बांद्रा टर्मिनस – अमृतसर सुपरफास्ट स्पेशल बांद्रा टर्मिनस से 14:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 20:30 बजे अमृतसर पहुंचेगी। यह ट्रेन 24 एवं 28 दिसंबर, 2025 को चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04696 अमृतसर – बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल अमृतसर से 04:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 11:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 23 एवं 27 दिसंबर, 2025 को चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, दाहोद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, मथुरा, दिल्ली सफदरजंग, पानीपत, अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर सिटी एवं ब्यास स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 04001एवं 04695 की बुकिंग 20 दिसम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मनरेगा में बदलाव पर सियासी संग्राम, डीएमके ने किया प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान

(जीएनएस)। नई दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को बदलकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के खिलाफ तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) खुलकर सड़क पर उतरने जा रही है। डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस ने मनरेगा के स्थान पर लागू किए गए 'विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025' के विरोध में 24 दिसंबर को पूरे प्रदेश में व्यापक विरोध प्रदर्शन का एलान किया है। इस फैसले के साथ ही केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच एक बार फिर टकराव की राजनीति तेज हो गई है।

डीएमके नेतृत्व वाले गठबंधन का आरोप है कि नया कानून मनरेगा जैसी ऐतिहासिक और गरीब-हितैषी योजना को व्यावहारिक रूप से खत्म कर देता है। गठबंधन का कहना है कि मनरेगा ने ग्रामीण गरीबों, खेत मजदूरों और कमजोर वर्गों को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देकर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की थी, जबकि नया विधेयक इस गारंटी को कमजोर करता है और रोजगार को सरकार की अनिश्चित योजनाओं पर निर्भर बना देता है। इसी कारण डीएमके और उसके सहयोगी दल इस कानून को मजदूर विरोधी और ग्रामीण भारत के खिलाफ बता रहे हैं। गठबंधन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे से राज्य के सभी जिलों, नगरों और पंचायत स्तरों पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। इस आंदोलन में मनरेगा के लाभार्थियों को विशेष रूप से शामिल किया जाएगा। डीएमके और गठबंधन दलों के जिला सचिव, विधायक, स्थानीय निकाय प्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ता 100-दिवसीय रोजगार योजना से जुड़े मजदूरों को संगठित करेंगे और सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। पार्टी का दावा है कि यह आंदोलन केवल राजनीतिक विरोध नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। डीएमके नेताओं का कहना है कि मनरेगा ने पिछले दो दशकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है और करोड़ों परिवारों को भुखमरी से बचाया है। उनका आरोप है कि नया 'विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' विधेयक रोजगार की कानूनी गारंटी को खत्म कर देता है और मनरेगा की मूल भावना के विपरीत है। डीएमके का कहना है कि केंद्र सरकार विकास के नाम पर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को कमजोर कर रही है और यह फैसला गरीबों की आजीविका पर सीधा हमला है।

सोना वायदा में 877 रुपये की गिरावट: चांदी वायदा में 1362 रुपये की तेजी: क्रूड ऑयल वायदा 77 रुपये फिसला

कमोडिटी वायदाओं में 26582.2 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 117983.26 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवरः सोना-चांदी के वायदाओं में 21428.21 करोड़ रुपये का हुआ कारोबारः बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 33011 पॉइंट के स्तर पर

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 144599.82 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 26582.2 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 117983.26 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का दिसंबर वायदा 33011 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 1720.01 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 21428.21 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 134021 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 134360 रुपये और नीचे में 133582 रुपये पर पहुंचकर, 134521 रुपये के पिछले बंद के सामने 877 रुपये या 0.65 फीसदी औंधकर 133644 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-गिनी दिसंबर वायदा 645 रुपये या 0.6 फीसदी की गिरावट के साथ 106960 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-पेटल दिसंबर वायदा 47 रुपये या 0.35 फीसदी की गिरावट के साथ 13395 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। सोना-मिनी जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 132252 रुपये के भाव पर खूलकर, 132575 रुपये के दिन के उच्च और 131912 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 729 रुपये या 0.55 फीसदी की गिरावट के साथ 131955 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-टेन दिसंबर वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 132625 रुपये के भाव पर खूलकर, 132875 रुपये के दिन के उच्च और 132258 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 132955 रुपये के पिछले बंद के सामने 656 रुपये या 0.49 फीसदी की गिरावट के साथ 132299 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 202899 रुपये के भाव पर खूलकर, 206280 रुपये के दिन के उच्च और 202656 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 203565 रुपये के पिछले बंद के सामने 1362 रुपये या 0.67 फीसदी की मजबूती के साथ 204927 रुपये प्रति किलो बोला गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 1375 रुपये या 0.67 फीसदी बढ़कर 205639 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 1371 रुपये या 0.67 फीसदी की बढ़त के साथ 205640 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

मेटल वर्ग में 2153.99 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा दिसंबर वायदा 2.05 रुपये या 0.18 फीसदी बढ़कर 1113.75 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता दिसंबर वायदा 1.6 रुपये या 0.53 फीसदी लुढ़ककर 300.85 रुपये प्रति किलो बोला गया। इसके सामने एल्यूमीनियम दिसंबर वायदा 15 पैसे या 0.05 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 282.35 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा दिसंबर वायदा 15 पैसे या 0.08 फीसदी की नरमी के साथ 181.25 रुपये प्रति

किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 2995.37 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जनवरी वायदा 5067 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5090 रुपये और नीचे में 5030 रुपये पर पहुंचकर, 77 रुपये या 1.51 फीसदी घटकर 5037 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जनवरी वायदा 74 रुपये या 1.45 फीसदी लुढ़ककर 5042 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस दिसंबर वायदा 354.2 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 355.2 रुपये और नीचे में 345.9 रुपये पर पहुंचकर, 356.2 रुपये के पिछले बंद के सामने 5.9 रुपये या 1.66 फीसदी गिरकर 350.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर पहुंचा। जबकि नैचुरल गैस-मिनी दिसंबर वायदा 6.1 रुपये या 1.71 फीसदी घटकर 350.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल दिसंबर वायदा 948 रुपये पर खूलकर, 6.9 रुपये या 0.73 फीसदी गिरकर 938 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 11463.11 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 9965.10 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1583.78 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 209.19 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 29.93 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 331.09 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 490.28 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2492.39 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 17224 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 80246 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 23444 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 360490 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 38828 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 18228 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 42083 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 112305 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 24281 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 40957 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स दिसंबर वायदा सत्र के आरंभ में 32969 पॉइंट पर खूलकर, 33160 के उच्च और 32969 के नीचले स्तर को छूकर, 54 पॉइंट घटकर 33011 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जनवरी 5100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 35.4 रुपये की गिरावट के साथ 148.7 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.5 रुपये की गिरावट के साथ 11.25 रुपये हुआ। सोना दिसंबर 139000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 149 रुपये की गिरावट के साथ 456 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 205000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 425.5 रुपये की बढ़त के साथ 4602.5 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1120 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 68 पैसे की नरमी के साथ 8.3 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 310 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 48 पैसे की नरमी के साथ 1.3 रुपये हुआ। पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जनवरी 5100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 41.9 रुपये की बढ़त के साथ 218.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस दिसंबर 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.85 रुपये की बढ़त के साथ 9.5 रुपये हुआ।

सोना दिसंबर 130000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 41 रुपये की बढ़त के साथ 490 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी दिसंबर 190000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 258 रुपये की गिरावट के साथ 546.5 रुपये हुआ। तांबा दिसंबर 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.7 रुपये की गिरावट के साथ 4.99 रुपये हुआ। जस्ता दिसंबर 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 72 पैसे के सुधार के साथ 2 रुपये हुआ।

मुख्यमंत्री का नई दिल्ली में क्रेडाई के नेशनल कॉन्क्लेव में प्रेरक संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए विकसित भारत के विजन को साकार करने में रियल एस्टेट क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

कन्स्ट्रक्शन में 'मेड इन इंडिया' का सुर और इमारतों में भारत की विरासत तथा संस्कार झलकाएँ : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात वेल-प्लांड अर्बन डेवलपमेंट सहित विकास का रोल मॉडल बना है
- गुजरात सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स तथा समयबद्ध परमिशन जैसी व्यवस्थाओं के कारण बड़े डेवलपर्स के लिए निवेश केन्द्र बना है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के नेशनल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए विकसित भारत के विजन को साकार करने में रियल एस्टेट क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो विजन दिया है, उसे पूर्ण करने में रियल एस्टेट क्षेत्र का योगदान बड़ा रहेगा।

भारत रत्न तथा पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के एक सप्ताह पूर्व आयोजित इस कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने कहा कि वाजपेयीजी ने सुशासन और 21वीं शताब्दी के भारत की नींव रखी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उस नींव को गतिपूर्वक आगे बढ़ाकर विकास का मजबूत आधार तैयार किया है।

देश की सबसे बड़ी अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र के रूप में भारत में 'हाउसिंग फॉर ऑल' के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी पक्का मकान मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस संकल्प को पूरा करने के लिए क्रेडाई तथा रियल एस्टेट क्षेत्र के अग्रणियों से केन्द्र एवं राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने का अनुरोध किया।

रियल एस्टेट डेवलपर्स की विशेष भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रियल एस्टेट केवल जमीनें, इमारतें या दीवारें नहीं हैं, बल्कि यह वह स्थल है, जहाँ परिवार के सपने समाए होते हैं, व्यापार-धंधे सफलता प्राप्त करते हैं और लोग साथ मिलकर अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं। उन्होंने डेवलपर्स से अपील करते हुए कहा कि हम ऐसे मकान बनाएँ, जिसमें भारतीयता की महक हो। विदेशी टेक्नोलॉजी से भले ही प्रेरणा लें, परंतु डिजाइन भारतीय रखें। कन्स्ट्रक्शन में 'मेड इन इंडिया' का सुर हो और इमारतों में भारत की विरासत तथा संस्कार झलकते हों; ऐसे निर्माण करें।

उन्होंने सस्टेनेबिलिटी तथा इनोवेशन पर बल देते हुए कहा कि पर्यावरणानुकूल घर, कार्यालय और सरकारी इमारतें बनाना जरूरी हैं। इसके लिए नए अनुसंधान एवं नवीनता को प्रोत्साहन देना होगा। उन्होंने बढ़ते शहरीकरण के चलते संसाधनों का संचालन करने के लिए दूरदर्शी आयोजन की आवश्यकता समझाई।

गुजरात के विकास का उल्लेख करते हुए श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि पिछले 25 वर्षों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात वेल-प्लांड अर्बन डेवलपमेंट सहित विकास का रोल मॉडल बना है। इतना ही नहीं; गुजरात देश का सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है।

उन्होंने कहा कि गुजरात में सिंगल विंडो क्लियरेंस, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स तथा समयबद्ध परमिशन जैसी व्यवस्थाओं के कारण डेवलपर्स निवेश करने के लिए आकर्षित हुए हैं। ग्रीन बिल्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, वॉटर कन्जर्वेशन तथा वेस्ट मैनेजमेंट को प्रोत्साहन देने के कारण गुजरात रियल एस्टेट के लिए श्रेष्ठ स्थान बना है।

गिफ्ट सिटी तथा धोलेरा स्मार्ट सिटी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के चलते ऐसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स विकसित हुए हैं। धोलेरा 920 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित हो रहा है, जहाँ सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस तथा डिफेंस जैसे उद्योग आ रहे हैं। अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे तथा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के कार्य पूर्णता के चरणों में हैं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन से गिफ्ट सिटी में प्लग एंड प्ले सहित ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है कि बिजनेस प्लेयर को यहाँ आने से पहले ही उत्तम सुविधाएँ तैयार मिल जाती हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत आत्मनिर्भर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा ईज ऑफ लिविंग का प्रतीक बनना चाहिए। इसमें इनोवेशन, टेक्नोलॉजी तथा सस्टेनेबिलिटी का संगम भी होना चाहिए। उन्होंने रियल एस्टेट से जुड़े सभी से लिवेबल व लवेबल, सस्टेनेबल और फ्यूचर-रेडी शहर बनाने का अनुरोध किया। इस नेशनल कॉन्क्लेव में क्रेडाई के चेयरमैन श्री बोमन ईरानी, प्रेसीडेंट श्री शेखर पटेल, प्रेसीडेंट इलेक्टेड श्री जी. राम रेड्डी और देश के विभिन्न राज्यों के क्रेडाई प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

महाजन में हरिमाउ शक्ति-2025 का सफल समापन, भारत-मलेशिया की सैन्य साझेदारी को मिली नई मजबूती

(जीएनएस)। महाजन (राजस्थान)। बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के बीच भारत और मलेशिया के बीच रक्षा सहयोग को और सुदृढ़ करते हुए राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'हरिमाउ शक्ति-2025' सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चले इस दो सप्ताह के अभ्यास ने भारत और मलेशिया के बीच भरोसे, आपसी समझ और रणनीतिक साझेदारी को एक नई ऊंचाई दी है। यह इस द्विपक्षीय अभ्यास का पांचवां संस्करण था, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं ने एक साथ प्रशिक्षण लेकर अपनी सामरिक क्षमताओं को और धार दी।

इस अभ्यास में भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट के 120 जवानों ने हिस्सा लिया, जबकि मलेशियाई सेना की 25वीं बटालियन के 70 सैनिक भी इसमें शामिल रहे। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद-रोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना, संयुक्त रणनीति विकसित करना और विभिन्न परिस्थितियों में एक-दूसरे के साथ प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता को मजबूत करना रहा। दोनों सेनाओं ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, जंगल युद्ध और आधुनिक युद्ध तकनीकों से जुड़े पहलुओं पर भी गहन प्रशिक्षण किया।

अभ्यास के दौरान रेड और सर्च ऑपरेशन, घात लगाकर हमला, हेलिकॉप्टर से कार्रवाई, ड्रोन और काउंटर-ड्रोन तकनीक, हेलिपैड की सुरक्षा तथा घायलों की त्वरित निकासी जैसे अहम सैन्य अभ्यास किए गए। जवानों की शारीरिक क्षमता और मानसिक मजबूती बढ़ाने के लिए कॉम्बैट शूटिंग और योग सत्र भी आयोजित किए गए, जिससे सैनिकों में अनुशासन, फुर्ती और एकाग्रता को बढ़ावा मिला।

'हरिमाउ शक्ति-2025' का एक प्रमुख आकर्षण एमआई-17 हेलीकॉप्टर के जरिए किए गए स्लिथरिंग ड्रिल और हेलीबोर्न ऑपरेशंस रहे। आपात परिस्थितियों में लो-होवर जंप, सैनिकों की त्वरित तैनाती और लाइव फायरिंग अभ्यास ने आधुनिक युद्ध के वास्तविक हालात का अनुभव कराया। इसके साथ ही कमांड पोस्ट एक्सरसाइज के जरिए नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक योजना और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के प्रभावी उपयोग का भी अभ्यास किया गया। गौरतलब है कि हरिमाउ शक्ति अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी और तब से यह भारत और मलेशिया में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। 'हरिमाउ' शब्द मलय भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ बाघ होता है, जबकि 'शक्ति' हिंदी और संस्कृत का शब्द है, जिसका मतलब ताकत है। इस तरह हरिमाउ शक्ति का अर्थ हुआ 'बाघ की ताकत', जो इस अभ्यास की भावना और उद्देश्य को दर्शाता है।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के संयुक्त सैन्य अभ्यास न केवल दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करते हैं, बल्कि क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रयासों को भी मजबूती प्रदान करते हैं। हरिमाउ शक्ति-2025 का सफल आयोजन भारत और मलेशिया के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों और रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

श्रीगंगानगर में सीमा से सटे इलाके में अवैध धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला, जर्मन दंपति समेत छह हिरासत में

(जीएनएस)। श्रीगंगानगर। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में अवैध धर्मांतरण से जुड़ा एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। श्रीकरणपुर कस्बे में किराए के मकान में प्रार्थना सभा की आड़ में कथित तौर पर लोगों को पैसों और प्रलोभनों का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किए जाने का आरोप लगा है। मामला सामने आते ही पुलिस, खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा तंत्र सतर्क हो गए हैं, क्योंकि यह गतिविधि सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक हो रही थी।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार देर रात 18 दिसंबर 2025 को श्रीकरणपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार के पीछे वार्ड नंबर-22 में एक भवन में संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं। स्थानीय लोगों ने बताया कि भवन के बाहर कई गाड़ियां खड़ी थीं और अंदर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे। भवन पर JW-ORG लिखा हुआ बताया जा रहा है। जब आसपास के लोगों को गतिविधियां असामान्य लगीं तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के दौरान पता चला कि वहां प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को एकत्र किया गया था। आरोप है कि सभा के दौरान हिंदू देवी-देवताओं और धार्मिक गुरुओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही थीं और लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा था। मौके पर यूपी नंबर की एक गाड़ी में सवार दो विदेशी नागरिक मौजूद थे, जिनके जर्मनी के निवासी होने की पुष्टि हुई। इसके अलावा केरल और राजस्थान नंबर की गाड़ियों से भी कई लोग वहां पहुंचे थे। पुलिस ने देर रात कार्रवाई करते हुए जर्मनी के स्वैन बॉज बेट जलेर और उनकी पत्नी सैंड्रा सहित कुल छह लोगों को हिरासत में ले लिया। अन्य आरोपियों में बलजिंदर सिंह खोसा, केरल निवासी मैथ्यू और उसकी पत्नी मारिया, कर्नाटक निवासी संतोष वर्गीसी तथा राजेश कंबोज उर्फ पोपी के नाम सामने आए हैं। हिरासत की खबर फैलते ही चर्च परिसर और थाने के बाहर बड़ी संख्या में हिंदू और सिख संगठनों के लोग एकत्र हो गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सीओ पुष्पेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।

स्थानीय संगठनों और ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे बॉर्डर क्षेत्र में विदेशी नागरिकों का बिना अनुमति प्रवेश प्रतिबंधित है, इसके बावजूद जर्मन दंपति को यहां बुलाया गया। बताया जा रहा है कि यह दंपति हाल ही में भारत-पाक सीमा के पास स्थित माझीवाला बॉर्डर क्षेत्र में भी घूमने गया था, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है।

अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस बात की गहन जांच कर रही हैं कि विदेशी नागरिक सीमा क्षेत्र तक कैसे पहुंचे, उन्हें किन लोगों ने सहयोग दिया और क्या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए बीकानेर रेंज के आईजी हेमंत शर्मा और श्रीगंगानगर की पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन के श्रीकरणपुर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों और सबूतों की गहराई से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गुजरात में कुत्ते के पिल्लों के साथ खेलते मिले शेर, VIDEO देख नहीं होगा यकीन

(जीएनएस)। अमरेली। गुजरात के अमरेली जिले में जंगली जानवरों की बढ़ती आवाजाही के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया। आमतौर पर शेरों को गांवों में पालतू जानवरों का शिकार करते देखा जाता है, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल उलटा है। अमरेली के राजुला इलाके के कोवाया गांव में एक शेर कुत्तों के छोटे-छोटे पिल्लों के साथ खेलता हुआ नजर आया। इस अनोखी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शेर पूरी शांति से गांव की गली में मौजूद है और पिल्लों के साथ खेल रहा है। न तो शेर आक्रामक दिखाई देता है और न ही पिल्ले उससे डरे हुए नजर आते हैं। यह दृश्य देखने वालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि शेर को आमतौर पर हिंसक और शिकारी स्वभाव का माना जाता है। उधर, राजुला क्षेत्र में ही एक और घटना सामने आई है, जहां एक शेर एक आवासीय बिल्डिंग के परिसर में घुस गया। कुछ देर तक परिसर में घूमने के बाद वह बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस जंगल की ओर लौट गया। हालांकि इस घटना से इलाके के लोगों में दहशत जरूर फैल गई।

यह पहली बार नहीं है जब अमरेली जिले में शेर या तेंदुआ रिहायशी इलाकों में घुसा हो। इससे पहले भी कई बार तेंदुए और शेर गांवों और सड़कों पर देखे जा चुके हैं। राजुला के छट्टड़िया रोड पर मनमंदिर के पास खुलेआम घूमते तेंदुए का वीडियो भी हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि जंगली जानवर गांवों में घुसकर पालतू पशुओं का शिकार कर रहे हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मांग की है कि जंगली जानवरों की रिहायशी इलाकों में आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए सख्त और प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।

वॉटरफॉल की सैर बनी दहशत की कहानी, तमंचे के बल पर नाबालिग छात्र-छात्रा से अश्लील हरकत, वीडियो बनाकर मांगी फिरौती

(जीएनएस)। झारखंड कि कोडरमा जिले से एक ऐसी शर्मनाक घटना सामने आई है जो इन दिनों चर्चा का विषय बन गई है। गुरुवार को दो छात्र-छात्रा कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक वृदाहा वॉटरफॉल घूमने पहुंचे थे। जब वह दोनों घूम रहे थे उसी वक्त उनके पास दो असामाजिक तत्व पहुंच गए। पहले बंदूक की नोक पर दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद आरोपियों ने दोनों नाबालिग छात्र-छात्रा को एक दूसरे के साथ अश्लील हरकत करने के लिए मजबूर किया और उसका वीडियो बना लिया। आरोपियों ने वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद दोनों नाबालिगों से कहा कि वह वीडियो वायरल कर देंगे। अगर दोनों नाबालिग ऐसा नहीं चाहते तो उन्हें 10 हजार रुपये देने होंगे। दोनों नाबालिग बच्चों के द्वारा असमर्थता जताते हुए पैसे नहीं होने की बात कही गई। लेकिन आरोपी नहीं माने जिसके बाद दोनों नाबालिगों ने अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से लगभग 4600 रुपये ऑनलाइन मंगवाए और दोनों आरोपियों को पेमेंट कर दिया। किसी प्रकार आरोपियों के चुंगल से छूटकर दोनों नाबालिग तिलैया थाना पहुंचे और अपने साथ वृदाहा वॉटरफॉल में हुई शर्मनाक घटना के मामले में शिकायत दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन मिलते ही तिलैया थाना पुलिस दोनों पीड़ित छात्र-छात्रा की निशानदेही पर आरोपियों की पहचान और उनकी धर पकड़ में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को दोनों छात्र-छात्रा अपनी बाइक से वृंदाहा वाटरफॉल घूमने गए थे। दोनों वॉटरफॉल घूमने के बाद वापस लौट रहे थे इसी बीच दो युवक वहां आ धमके और दोनों को पकड़ लिया। हथियार का डर दिखाकर दोनों के साथ मारपीट की और अश्लील हरकत करवाई। इस दौरान दोनों की वीडियो उन लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। जिसे वायरल करने की धमकी देते हुए दोनों से 10 हजार की डिमांड की थी।

मामले को लेकर थाना में आवेदन मिलते ही तिलैया थाना के पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार नहीं हो सके हैं लेकिन पुलिस का कहना है वह जल्द ही आरोपियों को पकड़ेंगे। वहीं दोनों नाबालिगों ने उनके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की है।

बाघ संग तस्वीर, शिव पूजा और महाआरती वनतारा के मुरीद हुए अनंत अंबानी के मेहमान लियोनेल मेसी

(जीएनएस)। दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में शुमार लियोनेल मेसी की लोकप्रियता किसी पहचान की मोहताज नहीं है। भारत में भी उनके चाहने वालों की संख्या लाखों में है। जब मेसी अपने GOAT इंडिया टूर पर भारत पहुंचे, तो उनके प्रति दीवानगी साफ नजर आई। इसी दौरे के दौरान गुजरात पहुंचकर मेसी का एक बिल्कुल अलग और अनोखा रूप देखने को मिला, जिसने उनके प्रशंसकों को और भी प्रभावित कर दिया। गुजरात में मेसी ने उद्योगपति अनंत अंबानी के महत्वाकांक्षी वन्यजीव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का दौरा किया। यहां उनका न केवल प्रकृति और वन्यजीवों के प्रति संवेदनशील पक्ष सामने आया, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ाव भी देखने को मिला। मेसी ने वनतारा में शिव पूजा और महाआरती में हिस्सा लिया, जिससे वे भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में रंगे नजर आए।

वनतारा भ्रमण के दौरान लियोनेल मेसी ने रेस्क्यू किए गए और संरक्षण में रखे गए कई वन्यजीवों को करीब से देखा। उन्होंने शेर, बाघ, तेंदुआ, हाथी, विभिन्न शाकाहारी पशुओं, सरीसृपों और अन्य दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण प्रयासों को समझा। बाघ के साथ ली गई उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खासा चर्चा का विषय बनीं, जिनमें उनका सहज और करुणामय अंदाज साफ झलकता है।

मेसी ने वनतारा की टीम के साथ संवाद किया और वन्यजीव कल्याण, पुनर्वास और संरक्षण से जुड़े कार्यों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे प्रयास न केवल जानवरों की रक्षा करते हैं, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए प्रकृति को सुरक्षित रखने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाते हैं।

वनतारा में बिताए गए समय के दौरान मेसी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से बेहद प्रभावित नजर आए। खेल जगत के इस दिग्गज खिलाड़ी को यहां करुणा, परंपरा और प्रकृति का अनोखा संगम देखने को मिला। यही वजह है कि वनतारा से निकलते वक्त मेसी केवल एक फुटबॉल आइकन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और वन्यजीव संरक्षण के प्रशंसक के रूप में नजर आए।

नाबालिग छात्रा की मौत पर टूटा प्रशासनिक सन्नाटा, आंदोलन के दबाव में मानी गईं मांगें, लापरवाह SI निलंबित, 12 आरोपी हिरासत में

(जीएनएस)। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के पीठ कस्बे में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाने से हुई मौत के बाद उपजे जनआक्रोश के आगे आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। दो दिन तक चले तनावपूर्ण माहौल और सर्वसमाज के धरना-प्रदर्शन के बाद गुरुवार शाम प्रशासन और पीड़ित परिवार के बीच सहमति बन गई, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ और क्षेत्र में हालात सामान्य हुए। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, बल्कि पुलिस की शुरुआती लापरवाही को भी उजागर कर दिया।

जानकारी के अनुसार पीठ निवासी नाबालिग छात्रा ने मंगलवार 16 दिसंबर की शाम जहर खा लिया था। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे पहले सीमलवाड़ा, फिर डूंगरपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए छात्रा को उदयपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान बुधवार 17 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप था कि घटना से पहले छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था और इसकी शिकायत पुलिस को दी गई थी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

छात्रा की मौत की खबर फैलते ही पीठ कस्बे में आक्रोश फैल गया। सर्वसमाज के लोग पीठ चौकी के सामने एकत्र होकर धरने पर बैठ गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और आरोपियों के घरों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। गुरुवार को हालात और गंभीर हो गए, जब जिलेभर से बड़ी संख्या में लोग पीठ पहुंचने लगे। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे।

इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने एक बार आरोपियों के घरों की ओर कूच करने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी, जिससे तनाव और बढ़ गया। हालात को संभालने के लिए दोपहर बाद आईजी गौरव श्रीवास्तव, कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी मनीष कुमार स्वयं पीठ पहुंचे और पीड़ित परिवार तथा सर्वसमाज के प्रतिनिधियों के साथ लंबी बातचीत की।

बैठक में पीड़ित परिवार की ओर से 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग रखी गई, लेकिन सरकार के तय नियमों के अनुसार 11 लाख रुपये की सहायता राशि पर सहमति बनी। इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया। सबसे अहम मांग यह थी कि छात्रा की शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने वाले पुलिस अधिकारी पर सख्त कदम उठाया जाए। इस पर एसपी मनीष कुमार ने पीठ चौकी प्रभारी एसआई मणिलाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की घोषणा की, जिससे आंदोलनकारियों में कुछ संतोष दिखाई दिया।

वहीं मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी जावेद, उसकी पत्नी, मां, बहन, भाई, पिता सहित सहयोग करने वाले कुल 12 लोगों को डिटेन कर लिया। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर प्रशासन ने उनके मकानों के पट्टों की जांच कराने और अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया।